करनैल सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 4797।

15 सितंबर 1988.

पंजाब भूमि सुधार अधिनियम (1973 का X) - धारा 8 और 9 - भूमि को अधिशेष घोषित किया गया - हालाँकि, भूस्वामी की मृत्यु के बाद कब्ज़ा लिया गया और किरायेदार को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की गई आवंटन के आदेश पर मृत्यु का प्रभाव, कहा गया - मृत भूस्वामियों के उत्तराधिकारी - क्या हस्तांतरण पर अधिशेष क्षेत्र के पुन: निर्धारण का अधिकार है।

माना गया कि सरकार के पास समय की सीमा के बिना अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने का अपरिहार्य अधिकार है और भूमि मालिक इसे वापस दावा नहीं कर सकता है लेकिन यह अधिकार दो अपवादों के अधीन है। यदि उपयोग से पहले भूमि मालिक की भूमि का कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अधिशेष क्षेत्र को फिर से निर्धारित करना होगा ताकि पुनर्निर्धारण पर जो भी अधिशेष पाया जाए उसका उपयोग किरायेदारों के पुनर्वास के लिए किया जा सके। चूँकि मृत्यु की तारीख से पहले कब्ज़ा नहीं लिया गया था, इसलिए ज़मीन मालिक की मृत्यु के बाद कब्ज़ा लेना और आवंटन का आदेश भी अधिकार क्षेत्र के बिना है और रद्द किए जाने योग्य है। (पैरा 9 और 10)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(ए) विवादित आदेश अनुलग्नक पी/एल को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जाए;

(बी) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भी जारी किया जाए

(सी) उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा और अनुलग्नक पी/एल से पी/3 की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति को समाप्त किया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने तक, विवादित आदेश (पी/एल) के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए।

1) याचिकाकर्ता के लिए वकील एस. रूपल।

प्रतिवादी 4 और 5 के लिए रविंदर चोपड़ा, वकील।

(2) एस. बराड़, डीएजी उत्तरदाताओं 1 से 3 के लिए।

प्रलय

गोकल चंद मितल, जे.

(3) , 13 मानक एकड़ और 71 यूनिट भूमि को कलेक्टर, रामपुरा फूल द्वारा अधिशेष घोषित किया गया था, - 22 अप्रैल, 1959 के आदेश के तहत, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट के तहत 1953 (इसके बाद इसे '1953 अधिनियम' कहा जाएगा) अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बावजूद, 15 फरवरी, 1983 तक, जब पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की धारा 9 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा करने या किसी बेदखल किरायेदार या भूमिहीन किसान को आवंटित करने के लिए ओर क़ब्ज़ा लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। , 1972 (इसके बाद '1972 अधिनियम' के रूप में संदर्भित), इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 28 मार्च, 1983 को कब्जा ले लिया और कलेक्टर एग्रेरियन, रामपुरा फूल ने 30 मार्च, 1983 के अनुबंध पी 3 के तहत मुकंद सिंह के हाथों में अधिशेष क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र भाग सिंह को आवंटित कर दिया।अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बावजूद, 15 फरवरी, 1983 तक, जब पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की धारा 9 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, अधिशेष क्षेत्र पर कब्ज़ा करने या किसी बेदखल किरायेदार या भूमिहीन किसान को आवंटित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। , 1972 (इसके बाद '1972 अधिनियम' के रूप में संदर्भित), कब्ज़ा लेने के लिए। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 28 मार्च, 1983 को कब्जा ले लिया और

कलेक्टर एग्रेरियन, रामपुरा फूल ने 30 मार्च, 1983 के अनुबंध पी 3 के तहत मुकंद सिंह के हाथों में अधिशेष क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र भाग सिंह को आवंटित कर दिया।

(2) जब मुकंद सिंह के पुत्रों को उपरोक्त बात का पता चला, तो उन्होंने मामले को आयुक्त के समक्ष अपील में उठाया और तर्क दिया कि 11 जनवरी, 1983 को मुकंद सिंह की मृत्यु हो गई थी और इसलिए, अधिशेष क्षेत्र के प्रश्न पर 1972 अधिनियम के अनुसार उनके हाथों में फिर से विचार करना चाहिए ओर अधिशेष क्षेत्र को फिर से निर्धारित किया जाए ।यदि कोई अधिशेष क्षेत्र उनके हाथों में पाया गया था तभी आवंटन करने का प्रश्न उठ सकता था।

(3) विद्वान आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुकंद सिंह की मृत्यु की वास्तविक तारीख सही ढंग से नहीं बताई गई थी और वह 28 फरवरी, 1983 को जीवित प्रतीत हुए, और इस प्रकार अपील को खारिज कर दिया। वित्तीय आयुक्त को संशोधन करने पर, यह पाया गया कि मुकंद सिंह की मृत्यु 1 जनवरी, 1983 को हुई थी, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उनके सामने पेश की गई थी और चूंकि मृत्यु की तारीख पर कब्जा भूमि-मालिकों का था, अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में मामले का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। संशोधन की अनुमति दी गई और आवंटन आदेश रद्द कर दिए गए, - आदेश दिनांक 12 मार्च, 1987, प्रतिलिपि अनुलग्नक पीआई।

4) उपरोक्त आदेश के खिलाफ, आवंटी का बेटा कमल सिंह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में इस न्यायालय में आया था।

(5) प्रस्ताव की सुनवाई में, शेर सिंह और अन्य बनाम योजना के वित्तीय आयुक्त, पंजाब और अन्य (1) को इस प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया गया था कि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा से, भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है और ऐसा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब्ज़ा राज्य सरकार द्वारा लिया गया है या उपयोगिता योजना के तहत आवंटन किया गया है। मामला डी.बी. में दाखिल किया गया।

7) 22 अप्रैल 1959 को कलेक्टर सरप्लस एरिया ने मुकंद सिंह के हाथ में 13 मानक एकड़ एवं 7जे इकाई घोषित की थी। 11 जनवरी, 1983 को मुकंद सिंह की

मृत्यु हो गई और वह उस भूमि के कब्जे में रहे जिसे अधिशेष घोषित किया गया था। 25 फरवरी, 1983 को, 1972 अधिनियम की धारा 9(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था और जब भूमि मालिक अधिसूचित समय के भीतर कब्जा देने में विफल रहे, तो कलेक्टर ने धारा 9(2) 1972 अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 मार्च, 1983 को कब्जा ले लिया। और आवंटन का आदेश 30 मार्च, 1983 को किया गया था। 1972 अधिनियम की धारा 8 के तहत, भूमि राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त केवल उसी तारीख को निहित होती है जिस दिन राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उस पर कब्ज़ा लिया जाता है। इस मामले में 28 मार्च 1983कब्ज़ा लिया गया, यानी 28 मार्च, 1983 को,ज़मीन मालिक की मृत्यु हो गई थी और यह देखना होगा कि अतिरिक्त क्षेत्र का मामला उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में फिर से निर्धारित किया जाना था या कब्ज़ा लेना था भूस्वामियों की मृत्यु के बाद कानून के अनुसार था।

(8) वित्तीय आयुक्त, हरियाणा बनाम श्रीमती के मद्देनजर मामला भूमि मालिक के उत्तराधिकारियों के पक्ष में समाप्त हुआ। केला देवी (2), उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय, श्रीमती। अजीत कौर बनाम पंजाब राज्य (3) (पूर्ण पीठ) और रंजीत राम बनाम वित्तीय आयुक्त (4) (पूर्ण पीठ), और शेर सिंह के मामले (सुप्रा) में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। शेर सिंह के मामले में (सुप्रा) दृष्टिकोण उपरोक्त निर्णयों के विपरीत नहीं लिया गया है, जो उसमें निहित निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है: -

“अधिनियम में अपवाद के रूप में जो कुछ भी शामिल है वह धारा 10 (ए) (बी) में देखा गया है। यदि अधिनियम के प्रारंभ के समय, सरकार द्वारा संबंधित अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है या जब यह विरासत का मामला होता है, तो मालिक अपनी सीमा के निर्धारण के लिए ऐसी भूमि को अपनी भूमि से बाहर करने का दावा कर सकता है। दूसरा अपवाद स्वयं धारा 10-बी के प्रावधान से बंधा हुआ है कि जहां धारा 10ए (ए) के तहत अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग किए जाने के बाद उत्तराधिकार खोला गया था, विरासत द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में निर्दिष्ट बचत नहीं होगी इस प्रकार उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में अपवाद लागू नहीं होगा।

संक्षेप में कहें तो, सरकार के पास अधिनियम के तहत उल्लिखित दो अपवादों के अधीन किरायेदारों के पुनर्वास* के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए बिना किसी समय सीमा के एक निरंकुश अधिकार था। यदि मामला उद्धृत भाग में देखे गए दो

अपवादों में से किसी एक में गिरता है तो सरकार किरायेदारों के पुन: निपटान के लिए भूमि का उपयोग करने का अधिकार खो देती है। ये अपवाद भी भूमि के उपयोग से पहले ही अस्तित्व में आते हैं। यदि उपयोग के बाद भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है या भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी लाभ नहीं ले सकते हैं और अधिशेष क्षेत्र का पुनर्निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

ऊपर।"

(9) विद्वान वकील उपरोक्त उद्धरण को पढ़े बिना उसी अनुच्छेद में निहित निर्णय के पहले भाग को पढ़ना चाहते थे जो इस प्रकार है:-

“यह सच है कि किसी मालिक की भूमि को अधिशेष घोषित करने के आदेश के साथ, किरायेदारों के पुनर्स्थापन के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सरकार को एक समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, अधिशेष घोषित भूमि पर अधिकार सरकार में निहित हो जाता है, जिसे किरायेदारों के बीच पुन: बंदोबस्त के लिए वितरित किया जाता है।यह एक अपरिहार्य अधिकार है जिसे सरकार सुरक्षित रखती है। अपीलकर्ता का यह तर्क सही नहीं है कि अधिशेष होने पर वह भूमि वापस पा सकता है अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए सरकार पर कोई समय सीमा लगाता हो। न ही ऐसा कोई प्रावधान है जो भूमि के मालिक को भूमि वापस लेने का दावा करने और यदि सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे वापस पाने में सक्षम बनाता है।

अवधि।"

यदि उपरोक्त प्रश्न को पहले देखे गए उद्धरण से अलग करके पढ़ा जाता है, तो मामले को भ्रमित करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यदि रिपोर्ट किए गए निर्णय के पूरे पैरा 9 को पढ़ा और समझा जाता है, तो मामला स्पष्ट और स्पष्ट है कि सरकार के पास अक्षम्य अधिकार है। समय की सीमा के बिना अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने का और भूस्वामी इस पर वापस दावा नहीं कर सकता है लेकिन यह अधिकार दो अपवादों के अधीन है कि यदि अधिग्रहण से पहले भूस्वामी की भूमि का कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अधिशेष क्षेत्र को फिर से निर्धारित करना पड़ता है। ताकि पुनर्निर्धारण पर जो कुछ भी अधिशेष पाया जाए उसका उपयोग किरायेदारों के पुनर्वास के लिए किया जा सके।

10) अब मामले के तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए, जो शेर सिंह के मामले (सुप्रा) से अलग नहीं हैं, भूमि मालिक की 11 जनवरी 1983 को मृत्यु हो गई और उसके बाद 1972 अधिनियम की धारा 9(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था। भूमि मालिक को कब्ज़ा सौंपना था और उसके बाद 28 मार्च, 1983 को धारा 9(2)के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में कब्ज़ा ले लिया गया था)1972 अधिनियम और हमारे समक्ष याचिकाकर्ता के पिता को आवंटन उसके बाद 30 मार्च, 1983 को किया गया था। इसलिए, घोषित अधिशेष क्षेत्र का उपयोग भूमि मालिक की मृत्यु से पहले नहीं किया गया था और न ही इसका कब्जा राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। . भले ही राज्य सरकार ने भू-स्वामी की मृत्यु से पहले कब्ज़ा ले लिया हो, जिसके हाथ में 1972 के अधिनियम की धारा 8 के आधार पर क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया था, भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होती। कब्ज़ा लेने की तारीख. चूँकि मृत्यु की तारीख से पहले कब्ज़ा भी नहीं लिया गया था, 28 मार्च को कब्ज़ा लेना और साथ ही 30 मार्च, 1983 का आवंटन आदेश भी अधिकार क्षेत्र के बिना है और विद्वान वित्तीय आयुक्त द्वारा उचित रूप से अमान्य कर दिया गया था।

(11) ऊपर दर्ज कारणों से, रिट याचिका योग्यता से रहित है और खारिज कर दी गई है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)
कैथल, हरियाणा